

## संयुक्त राष्ट्र निकाय ने NHRC की मान्यता का स्थगन

**स्रोत: द हिंदू**

जनिवा में स्थिति और [संयुक्त राष्ट्र \(UN\)](#) से संबद्ध [ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस \(GANHRI\)](#) ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#) की मान्यता को स्थगति कर दिया है।

- यह नरिणय [मानवाधिकार परिषद](#) और कुछ [UNGA](#) निकायों में भारत के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
- [GANHRI](#) उन संस्थानों को **A-स्टेटस** देता है जो मानवाधिकारों की रक्षा में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - वर्ष 1999 में NHRI के लिये मान्यता प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से **NHRC** को A-स्टेटस से मान्यता प्राप्त है, जसि उसने वर्ष 2006, 2011 और 2017 में स्थगन के बाद भी बरकरार रखा।
    - हालाँकि, वर्ष 2023 और 2024 में भारत के NHRC को लगातार दो वर्षों के लिये A-स्टेटस नलिंबति कर दिया गया था।
- [GANHRI](#) की नवीनतम रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षति है। हालाँकि, इसकी पछिली रिपोर्ट (वर्ष 2023 की रिपोर्ट) में स्थगन की सफिरशि के लिये कई कारण बताए गए थे। इनमें शामिल हैं:
  - **संरचना:** NHRC में सदस्यों की नयिकृति में पारदर्शति का अभाव,
  - मानवाधिकार जाँच की नगिरानी के लिये **पुलसि अधिकारियों की नयिकृति**
  - सदस्य पैनल में **लगि और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव**
  - NHRC "सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम" होने के लिये आवश्यक स्थितियों बनाने में भी वफिल रहा है।

और पढ़ें: [राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग \(NHRC\)](#)